श्री हंसराज भारद्वाज : मैंने जो जवाब दिया है । . . . (व्यवधान) . . .

श्री शंकर सिंह बाघेला : तो सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा इन्होंने कहा अन्य बातों के साथ-साथ तो वे अन्य बातें अगर इम्पोर्टेण्ट हैं, तो वे भी कही जाएं और दूसरा इलाहाबाद मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च-न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित किए जाने की सिफारिशें जो की हैं, वह सिफारिशें कब तक आप एक्जीक्यूट करेंगे ?

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमान् जी, जहां तक इन खंडपीठों का सवाल है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि जो जसवंत सिंह कमीशन की सिफारिशें थीं, हमने राज्य-सरकारों के पास भेज दी हैं और वे उसका अध्ययन कर रहे हैं० यू० पी० सरकार भी, मध्यप्रदेश सरकार भी और जब उनका उत्तर आएगा कि उन्होंने कहां बेंच बनानी है, नहीं बनानी है तब उसके बाद उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री शंकर सिंह बघेला : माननीय चेयरमेन सर, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास के अलावा कितने राज्यों के आपके पास परपोजल आए हैं और उन परपोजल के खिलाफ भी क्या कोई रिप्रजेंटेशन आपके पास आए हैं और आपकी इसमें क्या पालिसी है ? अब जैसे गुजरात में सौराष्ट्र में न्यायपीठ की बात है, कई लोग समर्थन करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, तो केन्द्र सरकार की क्या पालिसी होगी न्याय को डीसेंट्रलाइज करने की ?

श्री हंसराज भारद्वाज : सर, कोई भी परपोजल . . .

श्री सभापति : आपके पास आए हैं कुछ ऐसे ?

श्री हंसराज भारद्वाज : सर, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं । हमारे पास राज्य सरकारों से परपोजल आने पर ही उस पर गौर बात हो सकती है, गौर हो सकता है । हमारे पास जिन र ज्यों की संस्तुति आई थीं, उस पर गौर किया गया, कमीशन द्वारा देखा गया और उस सरकार का, उसके पास भेज दिया गया । उसके बाद हमारे पास कोई, जवाब नहीं आया । जब उनके जवाब आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी । यह मामला ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे इस, पर निर्णय हो जाए, यह मामला ऐसा है जिसमें हाईकोर्ट को भी कांफीडेन्स में लेना पड़ेगा और बार-एसोसियेशन को भी कांफीडेंस में लेना पड़ेगा और माननीय सदस्य को मालूम है कि यह किस प्रकार का सवाल है, इसमें बार-एसोसियेशन भी डिवाइडेड हैं, जजेज भी डिवाइडेड हैं । तो इसमें सबसे मिलकर लेठ र अच्छी तरह से तय करेंगे । महोदय , इस को किसी जगहपर एक सवाल को हल करने का प्रश्न नहीं उठता है । उत्तर प्रदेश में तीन जगह इस बात पर विवाद है—आगरा में, मेरठ में और इलाहाबाद में । तो इन सब बार एसोसिएशन के माननीय सदस्यों से हम लोग मिले हैं और हमारी सरकार की नीति है कि वह डेमोक्रेसी में ज्यादा-से-ज्यादा आदमियों को लेकर चले और इसमें कोई कट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए, यह हमारी जिज्ञासा है ।

MR. CHAIRMAN: All right. Question Hour is over. Now, Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Recommendations of High Level Committee on Ex-servicemen

*303. SHRI N. RAJANGAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the High Level Committee on the problems of Ex-servicemen to permit non-pensioner Ex-servicemen to count full militant service upto 5 years and 50 per cent beyond 5 years

for increments in Pay on re-employment have been accepted by Government ;

(b) if so, whether orders have been issued in this regard ;

(c) what are the recommendations of the High Level Committee on which the decision of Government is still pending; and

(d) when it is likely to be decided?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) and (b) In the case of ex-servicemen retrenched from service without a pension and/or service gratuity and in the case of Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned officers who joined pre-commission training or were commissioned after 10-1-1968 on their appointment in Government Service to unreserved vacancies, the exact orders on fixation of pay on re-employment in civil posts provide for grant of advance increments equal to the completed years of service rendered by them in the Armed forces on a basic pay equal to or higher than the minimum of the scale attached to the civil post in which they are re-employed. The pay so arrived at should not, however, exceed the basic pay last drawn in the Armed Forces. This provision is not applicable to other categories of non-pensioner ex-servicemen.

(c) and (d) There are only 3 recommendations of the High Level Committee on which a decision is pending.

One recommendation likely to be accepted and implemented relates to having ex-servicemen as a separate category in the 1991 Census. The matter is under active consideration of the Registrar General.

The recommendation regarding 'Rank for Rank' pension was considered by the IV Pay Commission but was not accepted by it. However, the matter is *subjudice* before the Supreme Court. Another recommendation relates to the constitution of a Parliamentary Committee to oversee the implementation of various schemes and facilities for ex-servicemen. The need for such a Committee is still under examination.

It is not possible to indicate a date by which a decision will be taken on the recommendations which are pending.

Boosting of Ground Water in Andhra Pradesh

*305. SHRI TALARI MANOHAR : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state.:

(a) whether it is a fact that Government are likely to receive technical or financial assistance from the International Development Association for boosting ground water in Andhra Pradesh ; and

(b) is so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) No, Sir. However, there is a proposal for obtaining Dutch Assistance for a project "Ground Water Minor Irrigation Schemes" in Andhra Pradesh.

(b) The main features of this project include :—

(i) construction and commissioning of bore wells, tube wells and infiltration wells;

(ii) rehabilitation of sick tube-wells;

(iii) updating of survey and investigation instruments for